296 मिलियन डालर रह गया है। यह देखा जा सकता है कि सरकार द्वारा अपनाई गई विनिमय दर तथा अन्य बृहत् आर्थिक नीतियों के परिणामस्वरूप विदेशी ऋण की वृद्धि में गिरावट आई है।

स्वैच्छिक एजेंसियों को भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायता

87. **श्री राम सिंह राठवा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्ष के दौरान प्रदान की गई सहायता-राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि यह राशि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों के लिये असमान रूप से दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद): (क) जी हां।

(ख) 31 मार्च, 1993 तक की पांच वर्षों की अवधि के दौरान, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई डी बी आई) द्वारा स्वैच्छिक एजेंसियों को स्वीकृत एवं संवितरित विवरण राज्य-वार सहायता में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) स्वैच्छिक एजेंसियों को निधियों की मंजूरी और निर्गम विभिन्न राज्यों से उनसे प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर आधारित होता है। यह सहायता के लिए मात्र औद्योगिक रोजगार उन्मुख गतिविधियों में लगी स्वैच्छिक एजेंसियों पर भी निर्भर करता है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायता पूर्वोत्तर क्षेत्र के कम विकसित राज्यों सहित अधिकांश राज्यों की स्वैच्छिक एजेंसियों को प्राप्त हुई है।

विवरण

(लाख रुपये)

1.4.1988 से 31.3.1988 तक राज्य-वार स्वीकृतियां एवं संवितरण

क्रम० सं०	राज्य	स्वीकृतियां	संवितरण
1.	बिहार	4.00	40.10
2.	उड़ीसा	46.77	43.13
3.	पश्चिम बंगाल	35.58	27.63
4.	असम	10.90	9.79
5.	मणिपुर	3.15	5.76
6.	मेघालय	1.60	1.25
7.	नागालैंड	5.53	15.67
8.	अरुणाचल प्रदेश	6.00	8.55
9.	मिजोरम	7.00	5.50
10.	पूर्वोत्तर क्षेत्र (सामान्य कार्यक्रम)	401.55	400.65
11.	हरियाणा	3.00	2.14
12.	राजस्थान	22.50	17.40
13.	उत्तर प्रदेश	5.95	4.95
14.	दिल्ली	31.90	26.60
15.	गुजरात	37.77	30.99
16.	मध्य प्रदेश	15.75	4.00

क्रम० सं०	राज्य	स्वीकृतियां	संवितरण
17.	महाराष्ट्र	162.99	123.15
18.	आन्ध्र प्रदेश	15.75	4.00
19.	कर्नाटक	47.75	35.03
20.	केरल	12.06	2.25
21.	तमिलनाडु	42.10	52.86
	जोड़	911.85	823.80

Excise Reliefs for Vanaspati and Edible Oils Industry

88. SHRI SHIV PRATAP MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Vanaspati and edible oils industry has sought major excise reliefs from the Ministry of Finance in the Budget for 1994-95; and

(b) if so, what are the details in this regard and steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) Vanaspati manufacturers' Association in their pre-budget memorandum, has suggested to fully exempt vanaspati from excise duty. Solvent Extractors' Association, in their pre-budget memorandum, has suggested to increase the maximum excise rebate limit for use of non-conventional oils.

(b) In view of the ensuring budget, it is not considered desirable to indicate the views of the Government in this regard.

Interest rate on Money Supply in the World Market

89. SHRI BHUPENDER SINGH MANN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the rate of interest on money-supply of various categories in the world market in comparison to rates of interest for the same prevailing in India;

(b) whether there is a great difference between the two rates; if so, the reasons therefor; and

(c) what steps Government are taking to reduce this difference so as to make Indian producers competitive in the world market?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) Interest rates on bank lending of some developed and developing countries are indicated below:

	As in March 1993 (Per cent per annum)
1. Malayasia	9.50
2. Mexico	21.31 (Average cost of funds)
3. Singapore	5.30
4. Korea	8.50
5. Japan	5.28
6. Belgium	12.00
7. U.S.A.	6.00 (Prime rate)
8. Germany	13.35

(Source: International Financial Statistics, International Monetary Fund, October 1993.)